'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2016-18
WPP Licence No.- U(C)-101/2016
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 15.03.2016
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी-22, अतुल ग्रोव रोड, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 23354841-42

Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com

● वर्ष : 19 ● अंक 8 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 1 से 15 मार्च, 2016

'लाल सलाम' से 'जय भीम'

भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। 1917 में रूस की बोलसेविक क्रांति का असर पूरी दुनिया में तब तक फैल चुका था। कार्ल मार्क्स ने वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार की थी। लेनिन, स्टालिन, ट्राटस्की आदि ने उसको अमली जामा पहनाया। वहां की परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने समाज का विश्लेषण किया और मार्क्स के विचार को लागू किया। साम्यवादी विचारधारा की मान्यता है कि दुनिया दो भागों में बंटी है - एक गरीब और दूसरा अमीर। इसे लुटेरा और कमेरा या शोषक और शोषित के रूप में भी हम जानते हैं। भारत के समाज की संरचना अन्य समाज से भिन्न है लेकिन भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों ने उसी चश्मे से देखा जो दूसरे देश के कम्युनिस्टों ने किया। कुछ कहना मुश्किल है कि यहां के कम्युनिस्टों ने यह ऐतिहासिक गलती करके देश का हित किया या अहित। अब तक चल रहे दलित आंदोलन को जातीय आंदोलन ही वे मानते रहे लेकिन धीरे-धीरे एक दशक से बदलाव आने लगा। यह बदलाव असफलता से तो कम मजबूरीवश ज्यादा आने लगा। इनका बौद्धिक चिंतन कितना कमजोर है कि ये असफलता से भी नहीं सीखे। मजबूरीवश तो कोई भी करता है, जो आज ये कर रहे हैं। कन्हैया कुमार जेल से छूटकर जब जे.एन.यू. में भाषण दिया तो 'लाल सलाम' का नारा ही नहीं बल्कि 'जय भीम' का भी लगा। वे सभी नारे लगे जो कुछ दलित लगाते हैं, जैसे - 'मनुवाद - मुर्दाबाद', 'ब्राह्मणवाद - मुर्दाबाद' आदि। कुछ पल के लिए तो भ्रम पैदा हो गया कि यह सभा वामपंथियों की है या अम्बेडकरवादियों की।

1980 के दशक में जब मैं जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में आया तो वहां पर मेरा साम्यवाद की विचारधारा का प्रशिक्षण शुरू हुआ। समझाया गया कि कामरेड दुनिया में दो ही जाति होती है, एक गरीब और दूसरी अमीर। मैं भी यही मानने लगा था। कुछ तो मनोवैज्ञानिक कारण था, गांव-देहात से आने वाला एक छात्र जे. एन.यू. की बौद्धिक बहस को देखकर चकाचौंध तो हो ही जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से छात्र राजनीति शुरू होती थी। कार्यकर्त्ता की भांति तो इस्तेमाल किया गया लेकिन समर्पण और क्षमता के हिसाब से कभी तराशने का मौका नहीं दिया और अंततः कार्यकर्त्ता ही बना रहा। इससे निराशा और बहिष्कृत भी महसूस करता था। आर्थिक परिस्थिति खराब होने की वजह से सिविल सर्विसेज की ओर ध्यान जाना मजबूरी हो गयी थी। संयोग से सिविल सर्वेंट बन भी गया और जे.एन.यू. की दुनिया से बाहर आया, तब जाना कि बाहर की दुनिया कुछ और ही है। भारत सरकार की सर्वोच्च सेवा में रहते हुए भी जातिवाद का दंश परोक्ष रूप से देखने एवं महसूस करने का अनुभव तो होता ही रहा। धीरे-धीरे एहसास हुआ कि जे.एन.यू. में जो सामाजिक समझ दी गयी थी, उसका तो बाहर के समाज से ज्यादा कुछ लेना-देना ही नहीं है। उधर धीरे-धीरे जे.एन.यू. प्रांगण में भी बदलाव आने लगा है, लेकिन अब देर हो चुकी है।

'लाल सलाम' और 'जय भीम' एक हो पाएंगें यह तो वक्त ही बताएगा। जो जातिवाद के द्वंद को कभी माने ही नहीं और केवल सर्वहारा और पूंजीवाद में बंटा समाज मानते रहे, इसका समंजस्य एक टेढ़ी खीर तो है। दलित, महिलाएं एवं पिछड़े चौराहे पर खड़े हैं कि उनका भला कैसे हो? कम्युनिस्ट क्या उनका भला कर पाएंगें, जब वे भारी उतार की ओर हैं। रूस में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभुत्व खत्म होने से दुनिया के कम्युनिस्टों की कमर टूट गयी। चीन भले ही एक साम्यवादी देश हो लेकिन अंदर से वह मुक्त आर्थिक व्यवस्था की जकड़ में आ गया है। अब भूमंडलीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की चपेट में पूरी दुनिया आ गयी है तो भारत उससे कैसे अछूता रह सकता है। क्या अब मार्क्सवाद को भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में लागू करना संभव है? रोहित वेमुला एक मुद्दा मिल गया है, जिसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रश्न यह उठता है कि लाखों जिंदा रोहित वेमुला की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? रोहित वेमुला की आत्महत्या क्या कोई असाधारण घटना थी? उसी हैदराबाद विश्वविद्यालय कैंपस में इसके पहले 9 दलित छात्र आत्महत्या कर चुके थे तो ये कहां सोए हुए थे? प्रतिदिन हजारों स्कूलों में दलित बच्चों के साथ दोपहर का भोजन सवर्ण बच्चे नहीं करते हैं। एक ही छात्रावास में अनुसूचित जाति/जन जाति के बच्चों के लिए अलग अलग विंग हैं और मेस भी अलग। क्या ये सारे भेदभाव आज के हैं? क्यों नहीं कम्युनिस्ट पहले सक्रिय हुए?

जब दलित-आदिवासी के अधिकार की लड़ाई जैसे - आरक्षण, आदि की हो, तब कम्युनिस्टों को समाज गरीब और अमीर में बंटा दिखता है और जब कोई ऐसी घटना घटे, जिसका राजनैतिक लाभ मिले तो मानो इनसे ज्यादा कोई शुभचिंतक हो ही न। यू.जी.सी. के द्वारा जो स्पेशल कांपोनेंट प्लान एवं ट्राइबल सब प्लान का पैसा शिक्षा पर खर्च होना चाहिए था नहीं हो पाता, तब ये कम्युनिस्ट कहां रहते हैं? प्रवेश एवं शिक्षक पदों को अक्सर नहीं भरा जाता तो उस पर इतना शोर क्यों नहीं मचाते? बंगाल, केरल, त्रिपुरा में इनकी सरकारें रही हैं, वहां तो आरक्षण लागू करके दिखाते। बंगाल में दलितों की सबसे ज्यादा आबादी है लेकिन आरक्षण सबसे कम लागू हुआ। सामंतवादी स्थानों तक में दलित नेता पैदा हो गए लेकिन जहां इनका प्रभाव रहा, वहां कोई नेतृत्व नहीं उभरा। 1997 में 5 आरक्षण विरोधी आदेश जारी हुए, उसकी लड़ाई अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनो का अखिल भारतीय परिसंघ ने ही लड़ी। तात्पर्य यह है कि जब-जब दलितों-आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों पर कुठाराघात होता है, तब तो इनका पता नहीं लगता। यदि उस समय ये खड़े होते तो शायद रोहित वेमुला जैसी घटनाएं होती ही न।

सारी कम्युनिस्ट पाटियों का श्रेष्ठ नेतृत्व सवर्णों के हाथों में है। ऐसे में कैसे 'लाल सलाम' और 'जय भीम' का एकीकरण होगा। जो लोग समाज को गरीब और अमीर के रूप में ही देखते हैं, वे कैसे देख पाएंगें कि भारतीय समाज जातियों का है। साम्यवाद जब जवानी पर था तब जातीय समस्या का प्रश्न का सम्बोधन नहीं किया तो क्या बुढ़ापे में इस अगूढ़ समस्या का क्या कुछ कर पाएंगें? अम्बेडकरवादी जनतंत्र में विश्वास करता है, जबकि साम्यवादी सर्वहारा की तानाशाही व्यवस्था में। कम्युनिस्ट भौतिकवाद में विश्वास करते हैं, जबकि अम्बेडकरवादी भाव और भौतिकवाद दोनो में। लेकिन ने कहा था कि सर्वहारा की सत्ता का जब चरमोत्कर्ष होगा तो राज्य की सत्ता की जरूरत नहीं रहेगी। क्या ऐसा कोई देश है जो बिना राज्यसत्ता के संचालित संचालित हो रहा हो। क्या यह एक कल्पना के अलावा कुछ और है? देश में ही लगातार कम्युनिस्ट पार्टियां सिकुड़ती जा रही हैं। तो ऐसे में दलित और आदिवासी इनके पास जाने की बजाय उसके पास जाएंगें जो इनको सहारा दे सके। 'लाल सलाम' और 'जय भीम' में सामंजस्य पैदा करने को किसी से क्या ऐतराज एक जनतांत्रिक देश में, लेकिन समाज अब इतना भोला-भाला नहीं रहा।

- डॉ0 उदित राज

डॉ0 उदित राज ने दलितों को निजी क्षेत्र में आरक्षण हेतु लोक सभा में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2016.

डॉ0 उदित राज, सांसद एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ ने लोक सभा में 'प्राइवेट सेक्टर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण विधेयक, 2016' पेश किया।

जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 'प्राइवेट मेंबर बिल' सरकारी बिल नहीं होता है। यह किसी मंत्रालय द्वारा पेश नहीं किया जाता है, बल्कि लोक सभा या राज्य सभा के किसी एक सदस्य द्वारा संसद में पेश किया जाता है, इसलिए सरकार से इस बिल को पास कराने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। जब लोगों का भारी जनसमर्थन एवं दबाव नहीं होता, इस तरह के बिल पास नहीं होते। इसलिए जब संगठन को मजबूत नहीं किया जाता इस प्रकार के अधिकार लेना मुश्किल का काम है। जहां तक सांसद के रूप में जिम्मेदारी का सवाल है तो डॉ0 उदित राज जी ने निजी क्षेत्र में आरक्षण का यह बिल पेश करके अपनी जिम्मेदारी निभायी है अब जिन लोगों को इसका लाभ लेना है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। यदि ये अधिकार हासिल करने हैं तो परिसंघ द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान में अधिक से अधिक लोगों को सदस्य बनाने में अपनी भूमिका निभाएं और आंदोलन को तन-मन-धन से गति दें।

डॉ0 उदित राज जी ने इस बिल के उद्देश्य एवं कारण में तर्क दिया है कि वर्तमान में केन्द्र सरकार और राज्यों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों को आरक्षण उपलब्ध है। एक समय समूह 'घ' पद ही केवल एक ऐसी श्रेणी थी जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व आनुपातिक रूप से सामान्य से अधिक रहा था, तथापि, सरकार की आउटसोर्सिंग नीति तथा संविदा आधार पर विशेषकर समूह 'घ' पद में सेवा के लिए व्यक्तियों को किराये में लेने के कारण सरकारी नौकरी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों की संख्या में काफी कमी आई है। अतः अनुसूचित जातियों और अनसूचित जन जातियों के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध अवसरों में कमी आई है।

उदारीकरण और निजीकरण के पश्चात् प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। तथापि, प्रावेट सेक्टर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों की मौजूदगी लगभग नगण्य है। वे स्टॉक मार्किट, प्राइवेट सेक्टर बैंक, मीडिया, प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और अन्य संबंधित क्षेत्र का भाग नहीं हैं। जहां अनुसूचित जातियों और जन जातियों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नगण्य है। सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों के लिए प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के अवसर सृजित करने हेतु प्राइवेट सेक्टर में नियुक्तियों और पदोन्नति के मामले में आरक्षण प्रदान करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए रियायतों और विशेष स्कीमों का उपबंध करना चाहिए।

आरक्षण पर प्रश्न-पत्र : दूषित मानसिकता का प्रतीक

यह कितनी अजीब बात है कि जिन शिक्षण संस्थानों से मानव संसाधनों का निर्माण होता है, वहां जातीय भेदभाव चर्मसीमा पर पहुंच चुका है। शिक्षण संस्थानों में जातीय आधार पर विद्यार्थियों का शोषण किया जाता है, उनको मिलने वाले स्कॉलरशिप बंद कर दिए जाते हैं, उनके परीक्षक सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की अपेक्षा कम नम्बर देते हैं, या जानबूझ कर फेल कर दिया जाता है। ऐसी घटनाएं कभी-कभी समाचार पत्रों, टीवी चैनलों की प्रमुख खबरें भी बन जाती हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, शिक्षा मंत्री तक शिकायतें पहुंचती हैं, लेकिन परिणाम क्या निकलता है? रोहित वेमुला की स्कॉलरशिप बंद कर दी गई, इसका उसने शू-साइड नोट में भी उल्लेख किया। इसको लेकर प्रधानमंत्री तो क्या पक्ष और विपक्ष में नहीं बल्कि भारत और दुनिया के तमाम देशों में इस खबर को संज्ञान लेते हुए सकारात्मक और नकारात्मक कार्यवाही की गई। इसका का परिणाम यह निकला कि जेएनयू जैसे शिक्षण संस्थान का मामला कोर्ट और तिहाड़ जेल तक पहुंच गया। यह मामला थमा ही नहीं था कि अभी हाल ही में फेसबुक के माध्यम से दो और ऐसे मुद्दे उभर कर सामने आए जिसे पढ़कर आप दंग रह जाएंगे। एक मामला गुजरात के 'सेठ वी एस लॉ कॉलेज, ऊंझा, उत्तरी गुजरात' का है। यहां वर्ष 2015-2016 विधि भाषा विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में - "Reservation Policy. Slow Poison". नामक विषय पर निबंध लिखने को कहा गया और दूसरा मध्य प्रदेश राज्य के माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं के पेपर में 'जातिगत आरक्षण देश के लिए घातक' विषय पर निबंध लिखने के लिए कहा गया।

गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों की प्रांतों में भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। गुजरात से ही हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी आते हैं। वे अपने को दलितों का सच्चे हितैषी बताते हैं। बताते ही नहीं उन्होंने भारतीय संविधान की शोभा यात्रा निकाल कर गुजरात में ऐतिहासिक कार्य भी किया था और जब वे पिछले लोकसभा चुनाव में विजयी हुए तो संसद भवन के गेट पर ही अपना माथा टेककर उसके प्रति सच्ची आस्था प्रकट की। मोदी जी ने अपने भाषणों में बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर को अपना आदर्श माना है। उन्होंने बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर की 125वीं जयंती वर्ष पर अनेकों कार्यक्रम और योजनाएं तैयार की। बाबा साहेब पर 10 व 125 रूपये का सिक्का, डाक टिकट जारी किए। लंदन जहां वे पढ़ने के दौरान ठहरे थे, उसे खरीद कर उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्मारक बनाकर दुनिया की नजरों में सर्वाधिक अम्बेडकरवादी घोषित किया। यहीं नहीं उन्होंने बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के जीवन से जुड़े स्थलों को भव्यता प्रदान करने के लिए सार्थक प्रयास किए। लेकिन इतना सबकुछ होते हुए भी उन्हीं के प्रांत में एक लॉ कॉलेज 'आरक्षण नीति को धीमा जहर' पर निबंध लिखवाता है, तो यह अपने आप में चिंता की बात हैं। जब यहां से निकलने वाले विद्यार्थी वकील बनेंगे, जज बनेंगे तो वे दलितों के प्रति किस प्रकार का भेदभाव करेंगे इसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है। वैसे भी इस देश की न्यायपालिका आरक्षण के विरोध में समय-समय पर आरक्षण विरोधी निर्णय देते रहे हैं। इसके विरोध में दलितों ने संघर्ष भी किए। एक बार तो भारत के प्रधान न्यायधीश की नियुक्ति को लेकर देश का तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. के आर नारायणन जी ने न्यायपालिका में दलितों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न भी उठाया था उसी के बाद प्रथम बार के बी बालाकृष्णन जी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने और बाद में सर्वाधिक लंबे समय तक देश के प्रधान न्यायाधीश बन सके। लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय में दलित प्रतिनिधित्व शून्य है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रवीण राष्ट्रपाल ने मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी को पत्र लिखकर उचित कार्यवाही करने का आग्रह किया है।

जहां तक मध्य प्रदेश जहां शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है, वहां के माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं परीक्षा के पेपर में 'जातिगत आरक्षण देश के लिए घातक' विषय पर निबंध लिखवाने की बात है, तो मन में बार-बार यह प्रश्न उठता है कि आखिर इस तरह के प्रयास क्यों किए जा रहे हैं? मध्य प्रदेश के महू छाबनी में ही बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर का जन्म हुआ था। प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार की मदद से उनके जन्म स्थल को भव्यता प्रदान की है और हर वर्ष वहां सरकारी स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। दलितों के प्रति ऐसी मानसिकता रखने वाली प्रदेश सरकार आखिर इस प्रकार के प्रश्न पत्र पूछने के लिए शिक्षण संस्थान को बाध्य कैसे कर सकती है? क्या विडंवना है दलित महापुरूषों को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बजाए आरक्षण को ही देश के लिए घातक सिद्ध किया जा रहा है। जब इस घटना पर प्रदेश के दलित मंत्री श्री लाल सिंह आर्या जी से संपर्क किया गया और इस विषय पर उनकी टिप्पणी जाननी चाही तो उनका स्पष्ट कहना था कि यह परीक्षा प्रश्न पत्र का मामला है, इसमें सरकार की ओर से ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया जाता है और वैसे भी प्रश्न पत्र तैयार करने का दायित्व शिक्षण संस्थान का होता है। मुख्यमंत्री महोदय ने इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए दोषियों को दंडित करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्णय लिया है और दोषियों को सख्त सजा अवश्य मिलेगी। अजीब स्थिति है मध्य प्रदेश जहां से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत आते हैं। उन्हीं के मंत्रालय द्वारा जब अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण कानूनी रूप लेता है तो उसे विज्ञापन के रूप में प्रचारित किया जाता है जिसमें दलितों की 'मूंछ' की जगह 'पूंछ' का उल्लेख किया जाता है। जब सम्यक भारत इसको उजागर करता है, तो बाद में दुबारा विज्ञापन प्रकाशित होता है। केन्द्रीय मंत्री महोदय जी के प्रांत से लगातार दलित उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन वे इस दिशा में लगातार चुप्पी लगाए बैठे हैं। वे कुछ बोलते क्यों नहीं? सामाजिक न्याय की अवधारणा को चरितार्थ क्यों नहीं करते?

उक्त दोनों ताजा घटनाओं पर प्रांतों की सरकारें क्या कदम उठाएंगी यह अलग बात है, लेकिन इस प्रकार की मानसिकता के लिए शिक्षण संस्थान कार्य करेंगे तो देश के अन्य संस्थानों से क्या उम्मीद की जा सकती है? आज देश में जातिवाद समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि उसका रूप बदल गया है और वह चरमसीमा पर पहुंच रहा है। राजनीतिक दलों में बैठे प्रवक्ता समस्या के समाधान के बजाए उलझाने में ही विश्वास रखते हैं। वे नहीं चाहते कि देश में अमन और शांति का वातावरण बन सके। भारतीय संविधान के अनुरूप सभी को उचित न्याय और सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले। वे नहीं चाहते कि इस देश में दलित वर्ग के सामाजिक-आर्थिक विकास की परिकल्पना साकार हो सके। यदि ऐसा नहीं है तो देश में अन्याय, असमानता, शोषण और जातिवाद का जहर घोलने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही क्यों नहीं की जाती? सरकार को बदनाम करने के लिए जो लोग इस प्रकार का दुसाहस कर रहे हैं, उन्हें सामने क्यों नहीं लाया जाता, उन पर सख्त कार्यवाही क्यों नहीं की जाती? उक्त ताजा घटनाओं पर दलित बुद्धिजीवी चिंतित नजर आ रहे हैं। देश की ज्वलंत समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसकी आड़ में इस देश के पूंजीपति और गरीबी के दुष्चक्र में फंसता चला जा रहा है। संसाधनों का उचित वितरण आज की आवश्यकता बन गया है। वक्त रहते इस दिशा में दलितों को अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। यहीं हमारे महापुरूषों की सदैव मांग रही है, हम उसी मांग को 'सम्यक भारत' पुनः उठाने का प्रयास 'दलित मीडिया' के रूप में कर रहे हैं। इसमें हम कहां तक सफल होते हैं, यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसके लिए आपका सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

जय भीम!!!

– के पी मौर्य, दलित चिंतक
कार्यकारी संपादक 'सम्यक भारत'
मे.09910770135

✦✦✦

शत्रु सम्पति (संशोधन और विधिमांयकरणों) विधेयक 2016 पर लोकसभा में डॉ उदिज राज जी का भाषण

डॉ उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : सभापति महोदया, यह बिल बहुत छोटा है, इस पर बहुत ज्यादा चर्चा करने के लिए नहीं बचा है। लेकिन हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों को सुना है, वह इसको धर्म के आधार पर बांटकर देख रहे हैं। इसको दस तरह से नही देखा जाना चाहिए। यह प्रापर्टी ज्यादातर राजा-महाराजाओं की है और इस देश क राजा-महाराजा चाहे जिस जाति या धर्म के रहे हों, पूर्व में उनकी सम्पतियों को अधिग्रहित किया गया है और उनको राष्ट्रीय सम्पति घोषित किया गया है। इस सबके पीछे एक बात यह भी है कि उन्होंने इसको कोई खून-पसीने से नही कमाया है। उस समय सामंतवादी व्यवस्था थी और उन्होंने जनता की खून-पसीने की कमाई को हड़पा था और उससे उन्होंने अपनी रियासतें बनायी थीं। अगर इन प्रापर्टीज को, जैसा कि हमारे विद्वान दोस्त हुकुम सिंह जी कह रहे थे कि इनका डिसपोजल हो जाना चाहिए। इसको कस्टोडियन के तहत न रखकर वेस्ट हो जाना चाहिए और संस्थाएं बनानी चाहिए जहां-जहां भी संभव हो सकता है।

दूसरा, यहां अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हमारी यह संसद है। यह सवा सौ करोड़ की इच्छा का कोर्ट है और वह पांच लोगों का कोर्ट है। केवल पांच जज बैठक एनएसजीसी के ऊपर फैसला इस संसद के खिलाफ दिया है तो यह संसद फिर उस पर कानून बना सकती है। संवैधानिक स्थिति यह है कि न्यायालय को इस देश में कानून को इंटरप्रेट करने का अधिकार है, कानून बनाने का नहीं है As per the Constitution of India, they are to interpret the law and not to make the law. This Parliament makes the law. कानून बनाने का काम हमारा है, उसकी चिंता नहीं होना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि law is always dynmic. Yesterday's judgment of the Supreme Court can be changed also with the time and space. ऐसी बात नहीं है कि जो 2005 में है, उसके बाद में हम आगे नहीं जा सकते। जो कानून कभी हाउस में बनाया हुआ है, वह हो सकता है कि आगे चलकर हम ही चेंज करें। चूंकि Law is always dynamic. ये स्टेटिक चीजें नहीं हैं, डाइनेमिक है। इसलिए इस बिल का हम समर्थन करते है।

इसके अलावा मैं एक अनुरोध और कहना चाहता हूं कि अन्य लोग जो इस तरह की गतिविधियों में इनवोल्व हैं तथा उन्होंने सम्पति खरीदी है और वह बाहर भाग गये हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी या जांच चल रही है। उन सम्पत्तियों को भी इसी क्लास में शामिल किया जाना चाहिए, उनकी प्रोपर्टीज को भी अधिकृत किया जाना चाहिए – चाहे वे किसी धर्म के हों, चाहें किसी भी जाति के हों, वह कोई भी हो सकता है तो इसको इस तरह से बांटकर नहीं देखा जाना चाहिए।

जहां तक टर्मिनोलोजी एनिमी की बात है, this term has not been coined by us. It has been coined by Congress itself. यह एनिमी प्रोपर्टी की जो टर्मिनालोजी है, इसे भारतीय जनता पार्टी ने कोइन नहीं किया है, आप ही ने कोइन किया है। We are carrying forward the same terminology. So, you should not have any objection over it.

अंत मे मैं माननीय गुह मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हुं कि उन्होंने इस तरह का स्टैप उठाया है। इससे लिटिगेशंस कम होंगे, देश में बहुत सारे लिटिगेशंस बढ़ते ही जा रहे हैं तो उनका डिस्पोजल भी होना चाहिए, मैं समझता हूं कि वह इससे होगा।

9 मार्च 2016

डॉ. उदित राज जी ने लोकसभा में 14 मार्च को रोहित वेमुला, बजट में दलितों के लिए आबंटित धन के दुरूपयोग, छात्रवृत्ति एवं छात्रावास का मुद्दा उठाया

डॉ उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) :

महोदय अभी हाल में हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक छात्र रोहित वेमुला ने आत्महत्या की, उससे पूरे देश के अन्दर एक उबाल सा आ गया और तमाम प्रगतिशील ताकतें, सेक्युलरिस्ट फोर्सेस और अन्य सभी ने इतना शोर मचाया और सबने सारा दोषारोपण हमारी सरकार पर मढ़ने का प्रयास किया, जैसे उस आत्महत्या की जिम्मेदार हमारी सरकार के कारनामें हों। इसलिए यहाँ इस बात को रखना जरूरी हैं कि इसके पहले आठ छात्र उसी यूनिवर्सिटी में आत्महत्या कर चुके थे। जिन आठ छात्रों ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी में आत्महत्या की थी क्या उसके लिए भी हमारी सरकार जिम्मेदार है। जब पहले छात्र ने आत्महत्या की थी उसके बाद दूसरे ने और फिर तीसरे, चौथे ने आत्महत्याएं की थी, उस समय अगर कुछ कदम उठाये गए होते तो रोहित वेमुला वाली घटना को रोका जा सकता था जो यूनिवर्सिटीज और यूजीसी में तमाम पैसा भेजा जाता है, अगर उस पैसे का एप्लीकेशन हुआ होता तो आज जो तमाम वेमुला जिंदा हैं। हैदराबाद का वेमुला तो जिंदा नहीं रहा, लेकिन आज भी इस तरह के तमाम वेमुला जिंदा हैं। देश के अन्दर आज भी हजारों स्कूल हैं जहाँ मिड डे मील दलित बच्चों के साथ में सवर्ण बच्चे नहीं खातें हैं। यह आज की नहीं पहले की परम्परा चली आई है। यह हमें विरासत में मिली है।

इसके अलावा चाहे एम्स में छात्र के द्वारा आत्महत्या की बात हो, दिल्ली, कानपूर, आई.आई.टी. का मामला हो या अन्य कॉलेजों के मामले हों, इस तरह की तमाम घटनाएं घटती रही हैं, लेकिन उनके पीछे कारण क्या रहे। उसके कारणों को समझना बहुत जरूरी है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस और आकर्षित करना चाहूंगा कि उसका कारण बजट का दुरूपयोग भी है। अगर इस बजट का एप्लीकेशन हुआ होता, सदुपयोग हुआ होता तो शायद इस तरह का अत्याचार, भेदभाव यूनिवर्सिटीज और कैम्पसेज में नही होता। मैं 2011-2012 के बजट की बात कह रहा हूँ। उस वर्ष में शेडयूल्ड कास्ट स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत 814 करोड़ रू दिए गए थे। जबकि केवल 87 करोड़ पहुंचा बाकी पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में केपिटल असैट्स में ग्रांट इन एड में लगा दिया गया। कहने का मतलब यह है कि 814 करोड़ रू में से केवल 87 करोड़ रू ही पहुंच पाये। रोहित वेमुला द्वारा आत्महत्या करने का यह भी एक मुख्य कारण था, क्योंकि उसे स्कालरशिप नही मिल पा रही थी और यह पहले से ही चला आ रहा है। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 3 हजार छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोका जा रहा था किसी तरह से हस्तक्षेप करके उन्हें परिक्षा में बैठने की इजाजत दिलवा दी गई। अब उनके एकाउंट्स सील हो गए हैं। क्योंकि जो स्कालरशिप केन्द्र से जाती है, राज्य सरकार को आगे उसे डिसपर्स करने चाहिए, जब तक वह पहुंचे नही, तब तक उनके एकाउंट्स डीसील नही होगें, उन्हे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा।

महोदया उसी तरीके से 2012-13 में 1047 करोड़ रू का आबंटन यूजीसी को स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान के तहत हुआ और खर्च 107 करोड़ रू हुआ और बाकी कैपिटल असैट्स के रूप में ग्रांट इन एड के रूप में। इसी तरीके से अभी तक जो पैसा केन्द्र से जाता रहा है। उसका दूरूपयोग होता रहा है। वही मेन कारण रहें हैं।

महोदया इसके अलावा जवाहरलाल यूनिवर्सिटी और हैदराबाद यूनिवर्सिटी का जो मामला उभरकर इस देश के सामने आया है उस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। 2013 में एक नेशनल मोनेटरिंग कमेटी फॉर एससी, एसटी, ओबीसी की बैठक हो रही थी, जिसमें मैं भी उपस्थित था। उसमें यूजीसी के चेयरमैन और एमएचआरडी के सैक्रेटरी भी थे। तब यह पता लगा कि यूजीसी ने केवल 3परसैन्ट एससीपी का पैसा खर्च किया था।

इत्तेफाक से उस कमेटी में मैं भी था, यह जनवरी 2013 की बात है। यूजीसी के चैयरमैन भी उसमें थे। उस समय सोचा गया कि केवल 3 परसेन्ट पैसा खर्च किया गया है, जो शेडयूल कास्ट के लिए दिया गया है। इसको मार्च तक किसी तरीके से स्कालरशिप के रूप में कन्वर्ट करके पूरा खर्च किया जाना चाहिए, लेकिन वह खर्च नही किया गया। यह चीज पहले से ही चली आ रही है कि केवल 3 परसेन्ट पैसा खर्च होता है। बजट में एससी, एसटी के छात्रों के लिए अलोकेशन तो चला जाता है लेकिन यह खर्च नही हो पाता है यह बड़े दुःख की बात है। आज दिल्ली में 5.2 परसेन्ट शेडयूल्ड कास्ट के लड़के ग्रेजुएट हो पाए हैं, जबकि सामान्य जाति के 31.4 परसेन्ट लड़के ग्रेजुएट हैं, तो ग्रेजुएशन करने का शेडयूल्ड कास्ट में बहुत कम परसेन्ट है। वही अगर लड़कियों का देखा जाए तो 1.3 परसेन्ट शेडयूल्ड कास्ट की लड़कियों का है और सामान्य कैटेगरी, सोशली एडवांस कास्ट का 26.2 परसेन्ट है। यह कांग्रेस की वजह से हुआ है।

मैं विशेषतौर से आपसे आग्रह करना चाहुंगा कि इसी तरीके से जो पैसा यहां से हॉस्टल के कंस्ट्रक्शन के लिए दिया जाता है आज इस देश में नितान्त आवश्यकता इस बात की है कि एससी, एसटी के छात्रों के लिए हॉस्टल बनायें जाने चाहिए, जोकि बनाएं नही जा रहें हैं। मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे एक प्रोविजन बनाएं।

✦✦✦

दिव्यागों के सशक्तिकरण के लिए तीन दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन

नई दिल्ली, 11 मार्च

श्री विजय सांपला, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री, केन्द्र सरकार, द्वारा सांसद डॉ0 उदित राज द्वारा बुद्धा एजुकेशन फाउंडेशन के अंतर्गत आयोजित की जा रही दिव्यांगों के लिए तीन दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन टेक्नियां इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, मधुबन चौक, राहिणी, दिल्ली-85 पर किया गया। इस कार्यक्रम में दित्यांगों सहित उत्तर पश्चिम लोक सभा क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। सांसद डॉ0 उदित राज के अलावा डॉ0 राजीव शर्मा - मेडिकल डायरेक्टर, महावीर हास्पिटल, डॉ0 रचना भारद्वाज - सुपरिंटेंडेंट किरन सेंटर, श्री संजना मित्तल - सीनियर कोर्डिनेटर - अष्टावक्रा इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलेशन साइंस एंड रिसर्च, डॉ0 प्रवीन सुमन - सीनियर डॉक्टर, सर गंगाराम हास्पिटल, डॉ0 इमरान नूरानी, सीनियर डॉक्टर, गंगा राम हास्पिटल, डॉ0 अमजद हुसैन - एच.ओ.डी., हियरिंग इंपैरमेंट ए.आई.आर.एस.आर., हरीश कुमार - एच.ओ.डी.डी.वी. ए. आई.आर.एस.आर., डॉ. धीरेन्द्र कुमार - एच.ओ.डी., सी.पी., कार्यक्रम में माजूद रहे।

श्री विजय सांपला जी ने इस अवसर पर उपस्थित दिव्यांगों सहित उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे जानकर बेहद खुशी हुई कि मेरे मित्र एवं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर पश्चिमी दिल्ली से लोक सभा सांसद डॉ उदित राज अपने क्षेत्र के विकास और लोगों की खुशहाली के लिए काफी कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि अभी कुछ दिन पहले ही डॉ0 उदित राज और बुद्धा एजुकेशन फाउंडेशन ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली मैं रहने वाली महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग के प्रशिक्षण का कार्य शुरू किया है। मुझे यह जानकर भी अति हर्ष हुआ है की डॉ उदित राज अपने क्षेत्र के स्कूलों में शौचालय एवं पीने के पानी का प्रबंध करने का काम तेज़ी से कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि आज जिस कार्यक्रम का मैं उद्घाटन करने आपके बीच आया हूँ, इसमें डॉ उदित राज और बुद्धा एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा मिलकर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उनके समस्त प्रकार कि समस्याओं का निदान करने एवं उनके अधिकारों की जानकारी हेतु 3 दिन की कार्यशाला का आयोजन किया गया है। हमारी सरकार हमारे माननीय लोकप्रिय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में दिव्यंगों के कल्याण के लिए काफी कार्यक्रमों की पहल की है। उनहोंने दिव्यंगों में वह कार्यक्षमता देखी है जो आज तक की सरकारों ने नज़र अंदाज़ किया। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक्सेसिबल इंडिया नाम के नीति का आरम्भ किया। हमारे प्रधान मंत्री जी के मन और दिल में हमेशा दिव्यंगों के शशक्तिकरण की सोच को अत्यंत महत्व दिया है। दो बार अपने मन की बात में भी देश के सामने उन्होंने इसका उल्लेख किया है कि सरकार को ही नहीं, परन्तु समाज को भी अपना दायित्व बखूबी निभाना होगा। उनकी और मेरी निरंतर यही सोच रही है की हमारा देश किसी भी वर्ग को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए श्री नरेन्द्र भाई मोदी ने विकलांग शब्द की पीडा को महसूस किया और दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल करना ही उचित समझा।

सम्बोधित करते हुए डॉ0 उदित राज, सांसद उत्तर-पश्चिम दिल्ली लोक सभा क्षेत्र ने कहा कि पुराने समय में जो लोग विकलांग होते थे, उन्हें समाज में सामान्य दर्जा नहीं दिया जाता था, और उन्हें सभी चीजों से दूर रखा जाता था। विकलांग होना पुराने जन्मों के पापों का प्रायश्चित माना जाता था और उनके साथ घोर भेदभाव किया जाता था। विकलांगता मानव निर्मित ही है और ऐसे व्यक्तियों के साथ कभी भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस तरह के कार्यक्रमों से ही इस भेद भाव को समाप्त किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया कि वे अगले वित्त वर्ष में हमारी लोक सक्षा क्षेत्र की सभी दसों विधान सभाओं में इस प्रकार के कार्यक्रम करवाने हेतु व्यवस्था कराएं।

डॉ0 उदित राज जी ने आगे कहा कि विकलांगों की सहायता हेतु केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलायी जा रही हैं। आज शुरू हो रही इस कार्यशाला में विकलांगों के लिए सरकारी प्रावधानों एवं उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। कानूनी जानकारी देने हेतु उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ वकीलों की टीम यहां तीनों दिन उपस्थित रहेगें। मै श्री विजय सांपला, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने अपना अनमोल समय इस कार्यक्रम हेतु दिया।

(सी.एल. मौर्य)
निजी सचिव
9899766882

✦✦✦

श्री विजय सांपला का स्वागत करते हुए डॉ उदित राज

दिव्यांगों के अधिकारों सरकारी योजनओं पर बनायी गयी उपयोगी पुस्तिका को प्रदर्शित करते हुए श्री विजय सांपला, डॉ0 उदित राज एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति

परिसंघ का महाराष्ट्र राज्य सम्मेलन संपन्न हुंआ

अनुसुचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ का महाराष्ट्र राज्य सम्मेलन 12 मार्च 2016 को अमरावती के संत ज्ञानेशवर संभागृह में बड़े उल्लास से सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. डॉ उदित राज और अमरावती के जिला अधिकारी मा. गिले साहब थे। सम्मेलन में महाराष्ट्र के विभिन्न जिलो के अधिकारी, कर्मचारी और छात्राओं ने उपस्थिति दर्ज की। सम्मेलन का आयोजन परिसंघ के महाराष्ट्र अध्यक्ष सिद्धार्थ भोजने ने किया था।

डॉ उदित राज के साथ महाराष्ट्र परिसंघ के नेतागण

सम्बोधित करते हुए डॉ0 उदित राज

सम्मेलन को मार्गदर्शन करते हुए डॉ. उदित राज जी ने कहा कि भूमंडलीकरण ओर निजीकरण द्वारा सरकारी क्षेत्रों को आज लगभग खत्म किया कर दिया गया है। इससे आरक्षण भी खत्म हुआ है। आरक्षण बचाने के लिए वर्तमान स्थिति मे जनआंदोलन की जरूरत है। मगर समाज में जनआंदोलन को नजर अंदाज करके नेताओं के ऊपर जिम्मेदारी डालकर उनकी आलोचना करने को ही आंदोलन समाज में शुरू हैं। आलोचना करके समाज का बुद्धीजीवी, कर्मचारी, अधिकारी आंदोलन से अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है। यह दुःखद् स्थिति है। हालंकि मैनें जाट और पटेल आरक्षण का आंदोलन का ब्योरा देते समय कहा कि ये आंदोलन किसी नेता ने नही किया बल्कि जिम्मेदारी निभाते हुए हर एक व्यक्ति ने किया। इसे नकारा नहीं जा सकता। हमारा समाज बंटा है इसीलिए समाज के नेता भी बंटें है। समाज को अभी संगाठित होकर अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, इसी से हम निजीक्षेत्रों में आरक्षण का आंदोलन तेज कर सकते हैं, और देश में भागीदारी तय कर सकते हैं। रोहित वेमुला की हत्या पर अपनी बात रखते हुए कहा कि रोहित की हत्या हुई है। इसमें दो मत नहीं है। इसके पहले भी हैदराबाद विश्वविद्यालय में 8 छात्रों ने आत्महत्या की है, और आज भी देश में लाखों रोहित वेमुला जैसे छात्रों का शोषण हो रहा है। शिक्षा संस्थान में इन छात्रों के साथ जातिगत भेदभाव किया जाता है। आज भी राज्य सरकार छात्रवृत्ति समय पर नहीं दी जाती है। इन छात्रों के लिए छात्रावास की कमी रही है। इनके इन शोषण के खिलाफ छात्रों को लड़ना पड़ेगा। उसी तरह डॉ उदित राज ने वामपंथियों के ऊपर हमला करते हुए कहा कि इन्होंने दलितों–आदिवासियों के विकास के लिए और निजी क्षेत्र में आरक्षण के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। पश्चिम बंगाल में दलित नेताओं का नेतृत्व वामपंथियों ने उभरने नहीं दिया। डॉ. उदित राज जी ने आखिर में अपनी बात समाप्त करते समय कहा कि परिसंघ को मजबूत करने के लिए कर्मचारियों, छात्रों व युवाओं को तेजी से कार्य करने और समाज को संगठित करने की जिम्मेदारी निभाने और उनको आंदोलन के लिए तैयार करने के लिए कहा।

इसी कार्यक्रम में अमरावती के जिला अधिकारी सम्मेलन का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि हम अधिकारी बने है समाज की बदौलत तो हमें समाज को कुछ देना भी है। हम जिस स्थिति में अधिकारी बनें हैं, उसी गरीब स्थिति में हमारा समाज जीवन जी रहा है। उसके उद्धार के लिए कार्य करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।

सम्मेलन में 'नोसेसवायएफ' के राष्ट्रीय अध्यक्ष डी हर्षवर्धन ने कहा कि जाटों ने अपने आरक्षण के लिए हरियाणा में 80 हजार करोड़ रू का नुकसान किया। निर्दोषो का कत्लेआम और महिलाओं से कुकर्म किया और इस हिंसक आंदोलन के सामने सरकार ने अपने घुटने टेक कर जाट अरक्षण के समर्थन में केन्द्रीय समिति गठित की। हम दलित आदिवासी ओ.बी.सी. अपने सामाजिक न्याय के लिए संवैधानिक और अहिंसक तरीके से आंदोलन करते है। निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए सरकार आज तक गंभीर नही है। इसका यह मतलब नहीं है कि दलित–आदिवासी ओ.बी.सी. हिंसा नही जानते हैं। जाट तो हरियाणा, पश्चिमी उत्तरप्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में पाये जाते हैं, मगर इस देश के दलित हर एक गांव–शहरों में है। ये हिंसात्मक आंदोलन करेगा तो देश का माहौल और देश भी लुटने के लिए कोई बचा नहीं पायेगा। ये चेतावनी हम सरकार को देते हैं। रोहित के हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए और लाखों रोहित को न्याय भी मिलना चाहिए और नोसेसवायएफ इसी के लिए संघर्ष कर रहा है।

इस कार्यक्रम की प्रस्तावना डॉ. रविद्र शिरसाठ और कार्यक्रम की भूमिका सिद्धार्थ भोजने जी ने रखी। सम्मेलन की शुरूआत डॉ उदित राज जी के स्वागत में मोटर साईकल रैली पूरे शहर से निकाली गई थी। कार्यक्रम के दौरान नोसेसवायएफ के विद्र्भ कार्यालय का उद्घाटन किया गया।

✦✦✦

परिसंघ की सदस्यता का विवरण भेजें

बार–बार आग्रह करने के बाद भी अभी तक अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की जो सदस्यता की रसीदें जारी की गयी थी, वापिस नहीं आ सकी हैं। परिसंघ के प्रदेश, जिला, ब्लाक इकाइयों के पदाधिकारियों व शुभचिंतकों, जिनके पास सदस्यता की रसीदें हैं, वे नाम, मोबाइल नं., जिला एवं प्रदेश लिखकर नीचे लिखे प्रारूप में अतिशीघ्र parisangh1997@gmail.com पर ईमेल करें।

सदस्य का नाम	मोबाइल नं.	जिला	प्रदेश

– डॉ0 उदित राज,
राष्ट्रीय अध्यक्ष

रोज होता है दलितों पर अन्याय

नागपुर 13 मार्च.

हैदराबाद विद्यापीठ के छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी संबधित युनिवर्सिटी का पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी आठ प्रताड़ित विद्यार्थियों ने आत्महत्या की है, दलित अत्याचार की घटनाएं रोज होती हैं देश में आज भी हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां दलित और सवर्ण बच्चे एक साथ भोजन नहीं करते हैं इस भेदभाव की जड़ें हजारों साल पुरानी है, लेकिन किसी तरह जो मामला मीडिया के माध्यम से बड़े स्तर पर उठता है राजनितिक पार्टियां भी बड़ा बवाल करती हैं, फिर वह प्रगतिशील हों तो कम्युनिस्ट दोनों विचारधारा वाले नेता दलित पर अन्याय होने का हवाला देकर चिल्लाने लगते हैं, उन्होंने कयुनिस्टों को घेरते हुए कहा कि केवल, बंगाल व त्रिपुरा में उनकी सरकार है, लेकिन वहां आज तक दलित नेतृत्व क्यों नहीं उभर पाया ?

दलित कठघरे में बांधा गया बाबा साहब को

डॉ उदित राज ने कहा कि डॉ बाबा साहब अंबेडकर जाति विहिन समाज की कल्पना करते थे, लेकिन यह बड़ी विडंबना है कि दलित में भी जातिवाद वाद है, समाज के कुछ राजनीतिक लोग दलित समाज मे ही जातिवाद का जहर घोल रहे हैं। बाबासाहब को भी दलित के कठघरे में बांध दिया गया, लेकिन वह किसी एक की विरासत नहीं हैं, बाबासाहब सबके हैं परन्तु उनकी सोच लेकर लड़ने के लिए कोई आगे नहीं आता है, केवल उनके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है।

जब दलितों को उनके अधिकार दिलाने की बात आती है तो यही राजनीतिक नेता तत्परता नहीं दिखाते हैं, लेकिन किसी दलित की मौत के बाद जरूर पहुंचते हैं, यह कहना है अनूसूचित जाति/जनजाति संगठन के अ.भा. परिसघ के अध्यक्ष व सांसद डॉ उदित राज का। वे दो दिवसीय नागपुर दौरे पर आते ही रविवार को रवि भवन में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। इस दौरान परिसंघ के प्रदेशध्यक्ष सिद्धार्थ भोजने, प्रदेश सचिव अर्चना भोयर, प्रमोद तभाने, दीपक तभाने, जीवन रामटेके उपस्थित थें।

रोहित वेमुला के दलित नहीं होने के सवाल पर डॉ उदित राज ने कहा कि वह दलित है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वह एक शोषित छात्र था। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह गलत था। सामाजिक व कानून व्यवस्था की समस्या भी है। इसके लिए मध्यम वर्ग के लोगों को ही आगे आकर बदलाव लाना होगा।

हर साल केंद्र सरकार के बजट में एससी–एसटी तथा महिला व बाल कल्याण योजनाओं की निधि में कटौती किए जाने का क्रम शुरू होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह सिलसिला वर्ष 1974 से लगातार जारी है, लेकिन उनकी ओर से इन योजनाओं के लिए निधि बढ़ोत्तरी की मांग की जा रही है, उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों का शोषण हो रहा है। वे चाहते हैं कि उनके सामाजिक संगठन परिसंघ के माध्यम से समाज के अधिकारी व कर्मचारी संबधित भेदभाव के खिलाफ खड़े हों।

✦✦✦

देश में भेदभाव उफान पर है और नकली आंबेडकरवादी समाज को विघटित कर रहे हैं

नागपुर 13 मार्च

मैं बैंक ऑफ इंडिया विदर्भ अंचल के सभी आंचलिक प्रबंधको से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने शीर्ष कार्यालय तक यह खबर पहुँचा दे की महासचिव रमेश मून के नेतृत्व में कार्यरत ऑल इंडिया बैंक ऑफ इंडिया एसी/एटी/ओबीसी एम्प्लॉईस असोशिएशन विदर्भ यूनिट के साथ त्रैमासिक सभाएं शीघ्र आरंभ करे, क्योंकि यह संगठन विदर्भ में बहुमत में हैं तथा परिसंघ के साथ संलग्न है। महासचिव रमेश मून के नेतृत्व मे कार्यरत इस बहुमत वाले संगठन से त्रैमासिक सभाएं नहीं लेकर बैंक ने अल्पमत में चल रहे संगठन को बहुमत में लाने हेतु परोक्ष रूप से मदद की है। भारत का संविधान कहता है कि जो बहुमत में हैं उसकी बात सुनी जाए लेकिन बैंक ऑफ इंडिया मे संविधान के विरूद्ध कार्य हो रहा है, अगर बैंक बहुमत का आदर नहीं करती है और गलती मे शीघ्र सुधार नहीं लाती है तो मुझे अपने तरीके से कार्यकरना आता है। इस प्रकार की स्पष्ट चेतावनी डॉ उदित राज सांसद लोकसभा तथा परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रेशम बाग स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले सांस्कृतिक सभागुह में दी। वे ऑल इंडिया बैंक ऑफ इंडिया एसी/एटी/ओबीसी एम्प्लाईस असोशिएशन विदर्भ यूनिट के वार्षिक सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि सभा को संबोधित कर रहे थे।

सम्मेलन में मंचपर बैंक ऑफ इंडिया नागपुर अंचल के आंचलिक प्रबन्धन मान चंद्रकांत पोपेरे, उपांचलिक प्रबन्धन मान सुधिरंजन पाढ़ी, सहायक महाप्रबंधक मान श्रीधरन, सहायक महाप्रबंधक मान डी. देवदास, कोकण ग्रामिन बैंक के अध्यक्ष मान कारापुरकर, संगठन के महासचिव रमेश मून, संगठन के अध्यक्ष मान लक्ष्मण बोरकर, कोषाध्यक्ष मान हरिश खोब्रागड़े, परिसंघ के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मान सिद्धार्थ भोजने, नागपुर शहर के अध्यक्ष मान दीपक तभाने, सुश्री अर्चना भोयर, सिदार्थ कांबले थे। इनके अलावा परिसंघ के मान माणिकलाल बोम्बुर्डे, सी. रामटेके, पूरे विदर्भ से बैंक कर्मचारी अधिकारी तथा अन्य विभागों के भी कर्मचारी/अधिकारी डॉ उदित राज को सुनने बड़ी संख्या में उपस्थित थे। परिसंघ के देविदास सांगोडे चन्द्रपुर भी उपस्थित थे।

डॉ उदित राज ने उपस्थित जन समुदाय से अपील की, कि अगर आपको आंबेडकरवाद की रक्षा करनी है तो प्रथम आपको असली आंबेडकरवादी की पहचान करनी होगी क्योंकि आजकल मौका परस्त नकली आंबेडकरवादी पैदा हो रहे हैं। दलित आदिवासी पर होने वाले हमलों, भेदभाव, दुराचार के पहले दलित/ आदिवासी से कोई वास्ता नहीं रखते केवल अप्रिय घटना घटित होने के बाद ही वे घड़ियाली आँसू बहाने पीड़ित परिवार से मिलने जाते है तथा मीडिया की सुर्खिया बटोरते है। जब रिजर्वेशन के विरूद्ध बनने वाला माहौल हो अथवा किसी जज की बे-वजह टिप्पणी हो मैंने निर्भीकता से सदन में मामला उठाया मगर बड़े दुःख की बात है मेरा साथ किसी ने नहीं दिया। ''नागपुर डॉ आंबेडकर की कर्मभूमि रही है, इतना ही नहीं मुझे भी इस भूमि से बहुत अपेक्षाएं है लिहाजा मैं इस अवसर पर आपको संगठित होकर कॉमन प्रॉबलम पर लड़ाई मे मेरा साथ देने का आव्हान करता हूँ। कार्यक्रम का संचालन मान दीलिप थेहगावकर ने किया तथा आभार प्रदर्शन सुमित दोडके ने किया, प्रस्ताविक महासचिव रमेश मून ने किया।

मिलिद स्कूल की बीस छात्राओं ने लेझीम नृत्य के साथ डॉ उदित राज को सभा-मंच तक ले गई। प्रसिद्ध गज़ल गायक अनिल भगत ने स्वागत गीत एवं सुगम संगीत प्रस्तुत किया। सेवानिवृत कर्मचारियों को शॉल तथा गुलाब का फूल देकर सत्कार किया।

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशिः

पांच वर्ष : 600 रुपए
एक वर्ष : 150 रुपए

Probe suicides of 8 Dalit students During UPA regime : Dr Udit Raj

"Suicide of Scheduled Caste students is not a new phenomenon. Before Rohith Vemula, eight more Dalit students in Hyderabad University had also committed suicide during the Congress regime. The earlier suicides of Dalit students never came into limelight. All these cases of suicide must be probed the Government should deal with this matter with complete transparency and ensure justice for all the victims, including Vemula," demanded Dr. Udit Raj, Member of Parliament (Lok Sabha) and National Chairman, All India Confederation of SC/ST Organizations during a press conference held at Ravi Bhavan in Nagpur on Sunday.

Dr. Raj lamented that though the media highlighted the Vemula incident at the national level, but the biggest irony is that in our society, the discrimination against Dalit students, which has been going on since centuries, rarely gets due prominence and attention. In 2012-13, the UGC spent only 2% of its total funds on welfare activities. This discrimination is not only prevalent in colleges but also very common in schools since many decades. Dr. Raj alleged that while the mid-day meals are a right of every school student, but more than 1000 schools in the country in the country which have a majority of SC/ST students never get mid-day meals.

Dr. Raj also said, "We have to start our work from the school level to remove caste discrimination and also implement this in every sector. Privatization is another field where reserved jobs are filled with contractual workers and Dalits experience caste discrimination."

When asked about the reduction in budgetary allocation to social justice department, Dr. Raj said that he will raise the issue in Parliament. He reiterated the demand for reservation in private sector, strict implementation of existing reservation norms and also to stop contractual employments.

Commenting on the recent JNU episode, Dr. Raj said that those trying to spread terrorist ideologies inside the JNU premises should be punished as per law, but cautioned the Central Government against tarnishing the reputation of the entire university and its students. Dr. Udit Raj also criticized Dalit leaders for their myopic vision and factional feuds revolving around their sub castes. He also alleged that many Dalit leaders try to use this inequality and discrimination for their narrow political benefits. Dr. Raj also said that while one cannot deny the reality of discrimination within Dalits by their own people, leaders of SCs and STs should try to end these internal inequalities and not blame the society for their backwardness. He made it clear that while Dr. Babasaheb Ambedkar worked for the equality of all castes, but people today are not following his path and vision.

Dr. Udit Raj

How Buddhists and Jains were Persecuted in Ancient Brahmin India

"…Hiuen-Tsang, who visited India from 629 to 645 AD, describes the influence of a south Indian Brahmin queen on her husband who ordered the execution of many thousand Buddhists including 8,000 in Madurai alone. Kalhana's Rajatarangani (written by a Shaivite scholar about 1149 AD and the first Brahmin account of India's historic past from the time of Yudishthira) relates that Mihirikula, the Hun ruler was converted by Brahmins (in 515 AD) and unleashed a wave of violent destruction on Buddhist monasteries in Punjab and Kashmir. He reports (verse 290 in book 1) that "crows and birds of prey would fly ahead eager to feed on those within his armies reach". He proudly proclaimed himself as the killer of three crores. … … – Buddhism that had been strong in India in the 7th Century was completely obliterated a century later."

There are many who seem to believe that brutality and bloodshed were the sole preserve of Muslim rulers and that Hindu rajas lived in an idyllic ocean of peace and tranquility. Unfortunately, an examination of the history of the Indian sub continent does not support such an uninformed opinion.

Gaining and retaining power is a brutal business all around the world, and has been so, all through history, with the possible exception within Buddhist societies where brute violence is rare. Many people genuinely believe that Hinduism has always been a tolerant religion that assimilated other peoples and ideas without bloody conflict. That is how they teach it! The ugly scars of brutality in the history of all peoples, are sanitized in school history books. The ruling powers, everywhere, want to play down the politics of past racial or religious persecution. This has the result in our case that many people hold the opinion that brutality and violence in India were exclusive to 'invaders' like the Greeks, Mongols, Turks and even the British. While these were the `invaders' easily condemned by the history books, it can be mentioned that most of the Arya, Scythian and Jat tribes, who came to India probably from central Asia, could also be described as 'invaders'.

For those tribes the word 'invasion' is an exaggeration. Most of north western India was fairly sparsely populated in ancient times and the great Indian cities (after the Harappan period) were mainly in the region of present day Bihar until the 6th century BC, so many alien tribes from less fertile areas of the north simply entered with little opposition, unnoticed even, by the local inhabitants. Pastoralists never made wars on each other and it was only with growing populations and urbanization that rulers of the evolving city states had to keep standing armies that were dedicated to protect but also attack for plunder!

There were therefore not many major conflicts in ancient times. But historians and story tellers, as usual, would exaggerate small tribal skirmishes to become great legends of prowess and minimize murderous bloodshed on their part.

After Ashoka's reportedly bloody battle against Kalinga, north India entered a thousand year period of relative peace under predominantly Buddhist rulers until the time of Harshavardhan who ruled from 606 to 647AD. But there had been many local wars between domestic kingdoms like the Cholas, Pallavas and Pandyas competing with the Satvahanas and the Guptas or the Rashrakutas, Gurjara Pratiharas and Palas in later times. There must have been considerable bloodshed in all these conflicts even if not much is recorded in Brahmin texts. These battles were however territorial and for loot, and religion does not seem to have been used to justify aggression.

Then there was a heady period of vigorous Brahmanical revivalism that rapidly gathered strength after the 7th century AD. It has to be remembered that this was not a `Hindu' revival because the idea of Hindu as a religion was not known at this time. During this Puranic period most people worshipped numerous animist deities usually presided over by Brahmin priests who chanted elevating Vedic hymns even though all the Vedic deities like Indra, Rudra and Nasatyas had now vanished. Many animist deities including and several goddesses were absorbed into a new Puranic Hinduism that included non Vedic deities like Shiv, Ganesh, Hanuman, Kubera, Kali, Durga and others and new philosophies like reincarnation, Karma and Dharma were borrowed from Buddhism and Jainism. Even the Vishnu of the Puranas was very different from the Vedic Vishnu. At this time Ram or Krishna were still heroes of legend and had not yet become deities for worship. A. R. Mujumdar in The Hindu History (1979) observes … "From 650 AD, perhaps to suit the needs of the age, Hindus suppressed true history and invented nice legends instead".

Many local rulers, probably at the urging of their Brahmin ministers and priests, now began to ruthlessly exterminate the previously dominant Buddhist and Jain faiths. Although the class of Kshatriyas had completely vanished from history during the thousand years of mainly Buddhist rule they were reinvented at this time to serve Brahmin interests. No doubt the rich lands and treasures of their defenseless monasteries and temples also gave material incentives to this religious fervor and many Buddhist and Jain stupas and monasteries were plundered and Hindu temples established at their sites.

Similar material motives had actuated religious persecutions in many lands including those by the Catholic and Protestant nobles in England during the much more recent period of the Reformation. There are many Hindu references to support this looting and plunder including the unedited versions of the original Puranas even though most Buddhist and Jain accounts were destroyed. Hiuen-Tsang, who visited India from 629 to 645 AD, describes the influence of a south Indian Brahmin queen on her husband who ordered the execution of many thousand Buddhists including 8,000 in Madurai alone. Kalhana's Rajatarangani (written by a Shaivite scholar about 1149 AD and the first Brahmin account of India's historic past from the time of Yudishthira) relates that Mihirikula, the Hun ruler was converted by Brahmins (in 515 AD) and unleashed a wave of violent destruction on Buddhist monasteries in Punjab and Kashmir. He reports (verse 290 in book 1) that "crows and birds of prey would fly ahead eager to feed on those within his armies reach". He proudly proclaimed himself as the killer of three crores.

This spawned a revival. Later, Brahmins paid killers to assassinate the Buddhist ruler Harshavardhana. With the plot discovered, as a Buddhist, he was unwilling to take life and so banished those 500 Brahmins involved in the conspiracy to a remote area south of the Vindhyas. Brahmins needed money for their purposes. Kalhan reports that several avaricious Hindu rulers looted the treasuries and even burned Hindu temples of the Shahi and Katoch rulers in neighboring areas long before the well known looting by the Muslim Mahmud Ghazni.

According to The Rajatarangani (IV/112), Chandradip, a Buddhist ruler of Kashmir, was killed by Brahmins in 722 AD. His successor Tarapida was killed two years later. The newly anointed Brahma-Kshastra (Rajput) rulers usurped power in the kingdoms of Sind and Kota. Graha Varman Maukhari, married to Harsha's sister, was treacherously killed by Sasanka, king of Gauda (Bengal). He proudly destroyed many stupas and cut down the sacred Bodhi tree at Gaya.

According to Gopinath Rao (East & West Vol. 35) the old tribal shrine at Jaganath Puri was usurped by Vaisnavas and the walls of the temple even today displays gory murals recording the beheading and massacre of Buddhists.

Epigraphica India Vol XXIX P 141-144 records that Vira Goggi Deva, a South Indian king, described himself as… "a fire to the Jain scriptures, a hunter of wild beasts in the form of the followers of Jina (Jains) and an adept at the demolition of Buddhist canon". It also records "the deliberate destruction of non Brahminical literature like books of Lokayat/ Carvaca philosophy by Brihaspati mentioned by Albaruni in the 11th century." The huge Buddhist complex at Nagarjunakonda was destroyed. According to Shankara Dig Vijaya, the newly anointed Brahma-Kshastra kings ordered every Kshatriya to kill every Buddhist young and old and to also kill those who would not kill the Buddhists. A Jain temple at Huli in Karnataka had a statue of five Jinas (Jain heroes) that was re carved into a Shaivite temple with five lingas.

E.S Oakley (in his 'Holy Himalaya') Rhys Davids (in 'Buddhist India') and Daniel Wright (in 'History of Nepal') quote several Nepalese and Kumoani documents showing that Buddhism had been the prevailing religion of the Himalayas with Badrinath and Kedarnath as Buddhist temples until Shankaracharya (788 - 820 AD) usurped them in the 8th century and the shrines at Badri and Kedar were then converted into shrines of Shiv and Vishnu. Wright records that "there had been a curious intermixture of the two religions with Buddhist priests officiating at the temples of Pashupati (Shiv) and all the four castes following the religion of Buddha." There is no evidence that Shankaracharya directed such persecution but what is likely is that power-hungry local rulers may have used his great name to lend legitimacy to their own destruction and looting. Many local hill rajas now invited Brahmins to their domains to get themselves elevated to the rank of Kshatriyas. And many were encouraged to attack Buddhist monasteries.

Several Nepalese accounts state that the followers of Buddha were ruthlessly persecuted, slain, exiled and forcibly converted – many converted rather than face death, humiliation or exile. The attackers tested their faith by making them perform 'Hinsa', or the sacrifice of live animals, that was so abhorrent to Buddhists and Jains. Many bhikshunis, or Buddhist nuns, were forcibly married and the learned Grihasthas were forced to cut off the distinguishing knot of hair on top of their heads. 84,000 Buddhist works were searched for and destroyed.

It is believed that Shankara introduced pilgrimages to those new Hindu holy places in the Himalayas for the first time to prevent their relapse into Buddhist or animist ways. As sufficient local Brahmins could not be found who were willing to preach in such remote places he imported Nambudri Brahmin priests from Kerala who, to this day, officiate at Badrinath, and Kedarnath.

Later as the mountain settlements grew other Brahmins like the Joshis and Pants from Maharashtra, Gairolas from Bengal and Negis from Gujarat were also invited to settle in the hills. Holy pilgrimages then ensured a constant influx of Hindu pilgrims with the presence of many traders, priests and rulers who had a vested interest in sustaining Hindu pilgrimages to these sacred spots.

Long held opinions admit reluctantly to the fact that oceans of blood were shed in the quest for power even among those who now consider themselves peace loving and spiritual Hindus. In India, as in every country, the hunger for political power and masculine dominance, and looting for treasure and girls, led to many examples of bloodshed and this became even more vicious when rulers used and abused the power of God-based religion to motivate their followers. The worst examples were undoubtedly the bloodshed in the name Christianity and Islam but there are also many examples among other people and their religions. Buddhism that had been so strong in India in the 7th Century had been completely obliterated a century later.

http://drambedkarbooks.com/2016/02/29/how-the-buddhists-and-jains-were-persecuted-in-ancient-brahmin-india/

Empowerment workshop for people with disabilities inaugurated

Shri Vijay Sampla, Hon'ble Minister of State of Social Justice and Empowerment, Government of India inaugurated a 3 day workshop on skill elevation, empowerment and awareness for people with disabilities organized by Dr. Udit Raj, Member of Parliament (Lok Sabha) under the aegis of the Buddha Education Foundation. The inaugural function was held at the Tecnia Institute of Advanced Studies, Rohini Delhi 85. Many people with disabilities and residents of the North West Delhi Parliamentary Constituency participated in the function. Many eminent speakers and subject matter experts such as Dr. Rajeev Sharma, Medical Director, Mahavir Hospital; Dr. Rachna Bharadwaj, Superintendent Kiran Centre; Mrs. Sanjana Mittal, Senior Coordinator, Ashtavakra Institute of Rehabilitation Science and Research; Dr. Praveen Suman and Dr. Imran Noorani from the Ganga Ram Hospital; Dr. Amzad Hussain, HOD (Hearing Impairment), Dr. Harish Kumar, HOD (DB) and Dr. Dhirendra Kumar, HOD (CP) were present at the inaugural function and will be conducting knowledge sessions throughout the 3 day workshop.

Shri Vijay Sampla said that he was extremely pleased that Dr. Udit Raj was conducting such programs for the development of his Constituency. He was also aware that Dr. Udit Raj and the Buddha Education Foundation were conducting a skill training program for women in cottage industries in North West Delhi. He also praised Dr. Udit Raj for taking the lead in building toilets and providing drinking water facilities in schools in his Constituency.

Shri Vijay Sampla also said that the program he was inaugurating would be a 3 day workshop to help resolve problems of people with disabilities as well as providing them awareness about their legal rights. He said that the Government, under the dynamic leadership of Prime Minister Narendra Modi, had started many programs and schemes for the welfare of people with disabilities. Our Prime Minister had seen a capacity to perform in people with disabilities, which had been ignored by many previous Governments. Keeping this in mind, the Government has launched the Accessible India program. He had also spoken about the problems faced by people with disabilities in his address to the nation in 'Mann ki baat.' Shri Vijay Sampla also said that the Government alone cannot solve all problems, society also has a very important role to play; the nation cannot progress while leaving behind any section of people.

Dr. Udit Raj said in his address that in the older days, people with disabilities were not considered to be equals and could not even access the common facilities of society such as temples and drinking water. Such discrimination continues even today, but maybe it is not as overt as it was earlier. However, he said that these awareness programs are the only way to remove this discrimination. Hence, Dr. Udit Raj requested the Hon'ble Minister that such awareness and skill elevation workshops be conducted in all 10 Assembly Constituencies represented by him in Parliament.

Dr. Udit Raj also spoke about the various schemes being run by the Government of India for the welfare of people with disabilities. The workshop being conducted would give the participants a complete overview of such schemes being run by the Government as well as knowledge about their legal rights and remedies. To ensure this knowledge, 3 senior advocates of the Supreme Court would also be a part of this workshop. Dr. Udit Raj also thanked Shri Vijay Sampla, Hon'ble Minister of State of Social Justice and Empowerment, Government of India for sparing his valuable time for this program.

PRESS RELEASE New Delhi,
11th March, 2016

✦✦✦

SEND DETAILS OF MEMBERSHIP OF CONFEDERATION

Despite repeated requests we did not get back the receipts of All India Confederation of SC/ST Organizations which were issued to Office-bearers of State/District & Block Units and well-wishers. Please send the following information immediately via e-mail to parisangh1997@gmail.com

Name of member	M. No.		Distt.
State			

- Dr. Udit Raj,
National Chairman

SEND MOBILE No. OF SUPPORTERS AND WELL-WISHERS

All India Confederation of SC/ST Organizations are requested to send their name, mobile number and district in two categories – Category 'A' is of Confederation leaders and important activists and 'B' of those who are social and supporters of Confederation. Please send e-mail to parisangh1997@gmail.com

Name	Mobile no.		District
State			

- Dr. Udit Raj,
National Chairman

Dr. Udit Raj raised SCP/TSP and interference of retired persons in Departmental Unions on 8th March

DR. UDIT RAJ (North West Delhi): Madam Speaker, I intend to raise the following two matters on the submission for the next week. Kindly grant permission and oblige.

1. Fresh guidelines should mandate earmarking of SCP/TSP funds from plan outlays at least 6 months before the commencement of the next financial year and schemes where benefits to SCs/STs are merely notional not be included in the Sub Plans. A specific institution should be set-up at Centre and State levels to allocate SCP/TSP funds to the Ministries/Departments, duly taking into consideration the developmental needs of SCs/STs, so that Ministries/ Departments can clearly show the schemes for the development of SCs/STs separately under the separate budget minor heads. The same institution should also be responsible for approvals and issue of sanctions and effective implementation and monitoring of the SCP/TSP. SCP/TSP funds should be deployed with particular focus on education, income generation and access to basic amenities in SC/ST localities in the country. Funds should be non-lapsable and non-divertible. SCP/TSP funds should be channelised only to such schemes where tangible benefits accrue to SC/ST individuals or households or groups or localities. Schemes taken up under the SCP/TSP should be closely monitored and the information should be hosted in the public domain so as to enable anyone to track every scheme. The NCSC and NCST should be strengthened with adequate professional expertise and provided with supporting manpower to undertake independent evaluation of SCP schemes of the Central Ministries and to give feedback to these Ministries. The NCSC can also recommend schemes which have the potential to best address the development needs of Scs to the concerned Central Ministries for inclusion in their Annual SCP Plans. The Nodal Department may also be empowered to clear the schemes proposed by the departments under the SCP only if the schemes fulfill the criteria of securing direct benefits to SC individuals, households or localities.

Meeting of Udhampur District Unit of Confederation held

Udhampur, 10th March 2016: A grand meeting of the All India Confederation of SC/ST Organizations was held at Udhampur under the leadership of Shri R K Kalsotra, State President Jammu & Kashmir of the Confederation. Other leaders present at the meeting included Shri B L Bhardwaj Gen Secy. of the Confederation, Dr. D D Dogra District President, Shri Shashi Kumar Syal, State Gen. Secy. Majdoor Dastkar Union, Shri D R Atri leader Panther Party, Shri S Ranjit Singh leader BSP, Shri Piar Bhagat and Shri Bishsn Dass State Coordinator, Shri Darshan Lal District President Majdoor Dastkar Union Udhampur, Shri Tara Nath, Dr. M R Bhamagi, Shri Anil Bhardwaj, Shri Aatish Bhardwaj, Shri Krishan Lal and Shri Ram. Shri Kalsotra also threw light on the working of the Confederation since its inception and its achievements made so far in fighting for reservation in promotion, reservation act, amendment of sro-294 and reservation in new recruitment policy. He urged all to whole heartedly work for the welfare of the organization and also made clear that the Confederation does not believe in back biting or infighting.

2. It has been observed that after retirement, employees continue to lead trade unions and/or associations of working employees. Complaints are being received from aggrieved employees in Ministry of Defense and Railways in particular. The Government must immediately take steps to rectify this practice.

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 19 ● Issue 8 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 1 to 15 March, 2016

From Lal Salam to Jai Bhim

The Communist Party was established in India in 1925. The results of the Bolshevik revolution in Russia in 1917 had spread throughout the world by then. Karl Marx's writings provided the ideological base for the spread of communism. Leftists in India looked at Indian society as a society similar to Russia, and then tried to look at the world as per Marx's views. They believe that there are only two classes of society – the rich and the poor; also known as the rulers and the ruled. Indian society is very different from other societies, yet Leftists tried to look at it as though it was the same as other countries. It is difficult to say whether this momentous mistake by the leftists was a boon or bane for the country. Till now, they had believed the Dalit movement to purely be a caste movement; however, some changes have started appearing in this decade. This is not out of choice, but mostly as a result of compulsion. Their Buddhist thought is so weak that even their failure could not teach them anything. When Kanhaiya Kumar was released from jail, during his speech at the JNU campus, slogans of

both 'Lal Salam' and 'Jai Bhim' were raised. All slogans which are used by Dalits, including 'Murdabad Murdabad', 'Brahmanvad Murdabad' etc were raised. For a second, it was confusing whether the rally was organized by leftists or Ambedkarites.

When I joined the Jawaharlal Nehru University in 1980, my education in socialism began. I was taught that there are only two classes in the world of comrades – the rich and the poor. Even I started believing in this. Some part of this was also due to psychology; a young boy from village will always be astounded by the intellectual debates in JNU. Student politics begins from international affairs. I was used as a worker, yet I never got an opportunity commensurate with my devotion and abilities and I stayed a worker. Due to this I felt depressed and removed from the mainstream. The financial pressures I faced meant that my attention would automatically be drawn towards the civil services. When I became a civil servant and left the world of JNU, I found that the outside world is

very, very different. While being in one of the topmost services of the Government, I got to see and feel caste discriminations. Slowly, I also found out that the socialism debated in JNU is very different from the socialism in the real world. Slowly, things in JNU also started changing, but it was too late.

Whether 'Lal Salam' and 'Jai Bhim' can come together is a question of time. Those who have never believed in caste discrimination and thought the world is divided into two groups of the rich and the poor; it is difficult for them to reconcile their views to caste politics and views. Will the communists be able to help them, when they themselves are in decline? The decline of communism in Russia has affected communists in other countries as well. Even though China is a communist state, internally it is in the grip of a communist economy. Now the entire world is in favor of liberalization, privatization and globalization – how can India be removed from this process? Is it now possible to implement Marxism in India? They have found an opportunity in the Rohith

Vemula issue which they are now trying to exploit. The question is why they do night fight for the thousands of Rohith Vemulas who are alive? In the same Hyderabad University campus, 9 Dalit students had committed suicide – where was their outrage then? In the same hostel, wings are different for SC/STs and their mess is also different. Has all this discrimination started today? Why were the Communists not active then?

When Dalits and tribals were fighting for their rights – reservation etc. the Communists saw the world only as the rich and the poor and now when such incidents take place and they want to take political advantage of it, it now appears that there are no better well wishers of SCs and STs than Communists. When SCP and TSP funds were not used for the welfare of Dalits, when backlog vacancies are not filled, then where are the Communists? Where they were in power, in West Bengal, Tripura and Kerala – at least there they should have implemented reservation. Bengal has the highest population of Dalits, yet their

percentage of reservation is the lowest. In 1997 when anti reservation orders were issued, the fight to remove them was fought by the All India Confederation of SC/ST Organizations. The moral is that when the Constitutional rights of SC/STs are in danger, then they are nowhere to be seen. If they had stood up during those times, then maybe incidents such as those of Rohith Vemula would not happened at all.

The leadership of all the Communist parties is in the hands of the forward castes. Then how can 'Lal Salam' and 'Jai Bhim' come together? Those who see society as the rich and the poor, how can they see that Indian society is divided into castes?

Dr. Udit Raj

✦✦✦

FIGHT FOR RESERVATION IN PRIVATE SECTOR BILL

Dr. Udit Raj, Member of Parliament (Lok Sabha) and National Chairman, All India Confederation of SC/ST Organizations has introduced the "Reservation in private sector for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Bill, 2016" in the Lok Sabha. As you are aware, a private member bill is not introduced by any Ministry or the Government; it is introduced in the House by a member of the Lok Sabha or the Rajya Sabha which is why it cannot be expected that the Government be responsible for passing of the Bill. Till the time people and society ensure massive amounts of support and pressure on Parliament for this issue, the Bill cannot be passed. Hence, if the organization and people's support is not strong, these rights will not be given by Parliament. Dr. Udit Raj has fulfilled his duties as a Member of Parliament by introducing this Bill. Now it is up to the people to fight for their rights and ensure that the Bill is passed. To give support to Dr. Udit Raj, all of you must participate very seriously in the membership drive of the Confederation and support the activities of the Confederation in every respect.

At present, reservation is available for people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in organizations of and under the State. The only place where SCs and STs were represented over the statutory reserved portion was in Class IV jobs, which have been diluted due to outsourcing and the contract system. Hence, the number of opportunities available for SCs and STs today is almost dismal.

After liberalization and privatization, the number of jobs in the private sector has increased considerably. However, the presence of SCs and STs in such jobs is almost negligible. They are not a part of the share market, private banks, media, private education sector, IT, telecommunication or any other field – where they are present, their numbers are negligible. The Government must make concessions and special schemes to encourage the private sector to open up to SCs and STs, and provide reservation.

Hence this Bill

11th March, 2016.

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com Computer typesetting by C. L. Maurya